



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27—फरवरी 2, 2018 (माघ 7, 1939)  
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27—FEBRUARY 2, 2018 (MAGHA 7, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	17	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	49	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	167	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 63
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 69
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 75
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	17	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	49	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	167	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	63
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	69
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	75
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I—खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

संस्कृति मंत्रालय

(राष्ट्रीय अभिलेखागार)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 दिसम्बर 2017

संकल्प

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का संविधान

सं. 19-1/2016-सी. सी.—संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प फा. सं. 19/2007-सी. सी., दिनांक 4 जुलाई 2011 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने संलग्नक के अनुसार भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि भारत के राजपत्र के भाग-I धारा-1 में प्रकाशित किया जाए।

एस. सी. मंडल, अवर सचिव

राष्ट्रीय अभिलेखागार

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का गठन

आईएचआरसी

गठन

(2 नवम्बर 2017 को यथानुमोदित)

## 1.0 पृष्ठभूमि

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग (नया नामकरण : भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति) की स्थापना सन् 1919 (दिनांक 21 मार्च, 1919 का शिक्षा विभाग का संकल्प संख्या 77) में एक परामर्शदाता निकाय के रूप में की गई थी। सरकार की नजर में इस निकाय का मत बहुत महत्वपूर्ण होता था और यह निकाय

- (i) ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अभिलेखों के उपचार,
- (ii) आकार और योजना जिसके आधार पर प्रत्येक अभिलेख का सूचीकरण सूची पत्र, कैलेंडर और पुनर्मुद्रण का कार्य किया जाना चाहिए;
- (iii) अभिलेखों के अनुसंधान और प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए वांछित धनराशि,
- (iv) अभिलेखों को संपादित करने के लिए सक्षम अध्येताओं के चयन और
- (v) अभिलेखों तक पहुंचने में जनता की समस्याओं के संबंध में जांच कर सकता था और सिफारिश कर सकता था।

भारत में विभिन्न राज्य सरकारों और देश के विश्वविद्यालयों तथा अग्रणी संस्थानों द्वारा समिति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने को बढ़ावा देने के लिए उनके बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अपने दिनांक 10 सितंबर, 1941 के अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार के संकल्प संख्या फा. 92-9/40 ई के द्वारा समिति के गठन में सुधार करने के लिए

कदम उठाए गए थे तथा इस समिति में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और अग्रणी संस्थाओं के नामित सदस्यों को भी शामिल किया जा सके।

जब से भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति<sup>1</sup> का गठन हुआ है तब से इसके अभिलेखों के रख रखाव और उनके उपयोग के संबंध में जनता की रुचि में योगदान किया है। भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार करते हुए गर्व का अनुभव किया है कि यह समिति और इसकी समितियों के ठोस प्रयासों का परिणाम है कि सूचना के विभिन्न नए स्रोत सामने आए हैं और हमारी धरोहर की रक्षा हुई है, अभिलेखों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनसे अनेक अध्येताओं को लाभ हुआ है, अभिलेखों के प्रयोग संबंधी सुविधाओं में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है तथा ऐतिहासिक साक्ष्यों को सत्यनिष्ठा और सत्यता के प्रति जनता की सोच में एक दृष्टिकोण ने जन्म लिया है। भारत सरकार ने समिति के इन प्रयासों तथा अन्य उपलब्धियों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए यह भी महसूस किया कि इस दिशा में अभी बहुत सा कार्य किया जाना शेष है और साथ ही अनेक समस्याओं का समाधान किया जाना है।

निजी अभिरक्षा में, विशेषकर जो संस्थानिक, धार्मिक अथवा वाणिज्यिक उदगम स्थलों में रखे अभिलेखों के सर्वेक्षण करने, उनका वर्णन तैयार करने, उन्हें व्यवस्थित करने अथवा उनका उपयोग करने के संबंध में बहुत ही कम व्यवस्थित प्रयास हुए हैं। प्रशिक्षित अभिलेखाधिकारियों के अभाव के चलते देश में अभिलेखों संबंधी कार्यों में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रदान की जा रही प्रशिक्षण सुविधाओं से अभिलेखी संपदा के स्वामियों से ऐसी कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो रही है जिससे यह पता चल सके कि राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण से उन्हें कोई खास लाभ पहुंचा हो। सरकार का मानना है कि देश की शिक्षा संबंधी उपलब्धियों में यह कमी एक गंभीर कमी है। इसलिए सबसे पहले एक ओर तो अभिलेखों और ऐतिहासिक सामग्रियों को संभाल कर रखने वालों और वहीं दूसरी ओर उनका उपयोग करने वालों के बीच सच्चे सहयोग से ही इन कमियों को दूर किया जा सकता है।

इस प्रकार के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार इसी विषय पर जारी अन्य सभी पूर्व संकल्पों को बर्खास्त करते हुए आईएचआरसी को निम्न स्वरूप में पुनर्गठित करने की स्वीकृति प्रदान करती है :

## 2.0 गठन

समिति का गठन निम्नप्रकार से किया जाएगा :

### 2.1 पदेन सदस्य

- |  |            |
|--|------------|
| 1. संस्कृति मंत्री<br>भारत सरकार                             | सभापति     |
| 2. सचिव, संस्कृति मंत्रालय<br>भारत सरकार, नई दिल्ली          | सदस्य      |
| 3. महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार,<br>भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य सचिव |

### 2.2 भारत सरकार के नामिति :

भारत सरकार 10 प्रसिद्ध इतिहासविदों और अभिलेखाधिकारियों को पुरालेखों की देखभाल करने संबंधी उनके विशेष ज्ञान और भारतीय इतिहास की सन् 1600 के बाद की अवधि के संबंध में उनके द्वारा दिए गए विशेष योगदान के आधार पर नियुक्त करेगी।

### 2.3 केंद्र सरकार के नामिति

भारत सरकार की निम्नलिखित एजेंसियों से तीन प्रतिनिधि

1. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
2. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
3. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली

<sup>1</sup>संस्कृति विभाग, भारत सरकार संकल्प संख्या एफ. 32-34/84-पुस्त. (पी एंड ए) दिनांक 15-10-1990 और शुद्धिपत्र, दिनांक 14-02-1992, फा. 18-15/96-प्रस्त।, दिनांक 25-11-96 फा.सं. 18-20/2002-एण्डए, दिनांक 10-06-2002, तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार, फा. सं. 19/2007-सीसी, दिनांक 12-06-2009 और 04-07-2011, फा सं. 18-26/2017-ए एंड ए दिनांक 2-11-2017 के तहत यथा संशोधित।

## 2.4 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों जिनके स्वयं के सुव्यवस्थित अभिलेख भंडार हैं, से प्रतिनिधि। यह नामिति निरपवाद रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखों का अभिरक्षक होना चाहिए।

## 2.5 विश्वविद्यालयों के नामिति

सन् 1600 के बाद का भारतीय इतिहास पढ़ाने वाले तथा मूल अभिलेखों के शोध और प्रकाशन को बढ़ावा देने वाले तथा स्वयं के अभिलेखागार स्थापित करने में आईएचआरसी के साथ सहयोग करने वाले भारत के विश्वविद्यालयों से 70 नामिति।

## 2.6 शैक्षिक संस्थाओं के नामिति

ऐतिहासिक अनुसंधान प्रकाशन को बढ़ावा देने, निजी और अर्ध निजी अभिरक्षा में स्थित अभिलेखों का सर्वेक्षण और खोजबीन के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, उन शैक्षिक संस्थानों से 20 नामिति

टिप्पणी (पैरा 2.5 और 2.6) : विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं के नामिति व्यक्तियों में अकादमिक विशेषता के साथ उनका मूल शोध कार्य में उल्लेखनीय योगदान होना चाहिए। ये सभी नामिति सरकार द्वारा उनके नामांकन अनुमोदित और अधिसूचित करने के पश्चात् ही भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान समिति के सदस्य होंगे।

## 3.0 भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान समिति (आईएचआरसी) की कार्यवधि

पदेन सदस्यों को छोड़कर समिति के सदस्यों को निम्नप्रकार से 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा :

5 वर्ष की पूर्णावधि के लिए सभी नियुक्तियां और पुनर्नियुक्तियां उसी तिथि से एक साथ की जाएंगी। उक्त 5 वर्ष की अवधि के दौरान त्यागपत्र अथवा अन्य कारणों से रिक्त हुए पद को पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं भरा जाएगा बल्कि शेष बची अवधि के लिए भरा जाएगा।

## 4.0 समिति का कार्यक्षेत्र

(क) सृजकों, अभिरक्षकों और अभिलेखों प्रयोक्ताओं के बीच अभिलेखों के उपचार, परिक्षण और उनके प्रयोग संबंधी विचारों और अनुभवों और पुरालेखों तथा ऐतिहासिक अभिलेखों के परिरक्षण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना तथा इस संबंध में सरकारी अथवा गैर सरकारी निकायों के उपयोग के लिए सिफारिश करना।

(ख) शोध की अपेक्षा वाली ऐतिहासिक समस्याओं, विशेषकर समस्याओं के बारे में जिन पर बहुत कम काम हुआ है या फिर कोई काम ही नहीं हुआ है, से संबंधित पुरालेखों पर चर्चा करने और शैक्षिक सत्रों आयोजन करने वाले मंच के रूप में कार्य करना। इस शैक्षिक सत्र में सन् 1600 के बाद के भारतीय इतिहास से संबंधित नए खोजे गए मूल अभिलेखों पर आधारित शोध पत्रों को पढ़ा जाएगा और उन पर चर्चा की जाएगी। ये शोध पत्र या तो समिति के सदस्यों के द्वारा लिखे होने चाहिए या फिर अन्य अध्येताओं द्वारा लिखे पत्र उनके माध्यम से संप्रेषित होने चाहिए। इस प्रकार के सभी पत्रों को परिचालित करने से पूर्व संपादकीय समिति, जिसका गठन इसी प्रयोजन के लिए किया गया हो, से अनुमोदित कराना जरूरी है। (नीचे पैरा 6.2 देखें)

(ग) विश्वविद्यालयों, ग्रंथागारों, संग्रहालयों, शैक्षिक संस्थाओं और विशेषकर क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समितियों और ऐसे ही स्थानीय निकायों के सहयोग से निजी और अर्धसरकारी अभिरक्षा (सांस्थानिक, धार्मिक और व्यापारिक अभिलेख) में मौजूद सामग्री के उद्धार और उसके उपयोग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में किए गए कार्य संबंधी सूचना के प्रसारकर्ता के रूप में कार्य करना।

(घ) आमतौर पर अभिलेख और ऐतिहासिक पांडुलिपि भंडार गृहों के बीच तथा शोधकार्यों में रूची रखने वाले निकायों के बीच माध्यस्थ का कार्य करना।

(ङ) इसकी गतिविधियों संबंधी कार्यवाहियों और रिपोर्टों की बुलेटनों को प्रकाशित करना तथा इसके लक्ष्यों को बढ़ावा देने वाले मुद्दों को प्रकाशित करना।

## 5.0 समिति की बैठकें

समिति की बैठक वर्ष में एक बार ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां पर अभिलेख सामग्री की प्रचुरता हो। प्रत्येक सत्र में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी।

- (क) एक आम बैठक सचिव द्वारा देश में की गई अभिलेखीय प्रगति पर प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की समर्पित होगी।
- (ख) सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के साथ-साथ उन अभिलेखों के रखरखाव और उनके प्रयोग, जिन्हें सदस्यों द्वारा उल्लिखित किया गया हो, से संबंधित समस्याओं पर और समिति के तत्वाधान में कार्यरत विभिन्न निकायों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए कार्य बैठक का आयोजन करना।
- (ग) सन् 1600 के बाद भारतीय इतिहास से संबंधित मूल अभिलेखों पर आधारित शोधपत्रों को पढ़ने और उन पर चर्चा करने के लिए शैक्षिक सत्रों को आयोजन करना। ये सत्र रुचि रखने वालों के लिए खुले रहेंगे।

समिति की बैठकों की अध्यक्षता पदेन सभापति द्वारा की जाएगी तथापि, उसे अपनी अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ सदस्य को सभापति नामित करने का अधिकार है।

#### 6.0 भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान समिति (आईएचआरसी)

आईएचआरसी किसी विशेष समस्या के मामले में जांच की अपेक्षा होने पर एक या अधिक समितियों को नियुक्त कर सकता है। ये समितियां अपनी रिपोर्टें इस समिति को प्रस्तुत करेंगी।

##### 6.1 स्थायी समिति

स्थायी समिति का संरचना और कार्य निम्न प्रकार होंगे :

##### 6.1.1 संरचना

- |   |                   |
|---|-------------------|
| (क) सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार                                   | पदेन सभापति       |
| (ख) भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले समिति के 5 सदस्य                | सदस्य             |
| (ग) अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार, नई दिल्ली          | पदेन सचिव         |
| (घ) अभिलेख उपनिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार, इस समिति से संबंधित | पदेन संयुक्त सचिव |

##### 6.1.2 कार्य :

स्थायी समिति, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर समय-समय पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी। इसके पास भेजी गई रिपोर्टें और मामलों पर विचार करेगी और समिति की बैठक की कार्य सूची पर अपना मत प्रकट करेगी तथा वे सभी कार्य करेगी जो उसे भारत सरकार अथवा समिति के सभापति द्वारा सौंपे जाएंगे। सामान्यतः इसकी बैठकें वर्ष में दो बार होंगी।

#### 6.2 संपादकीय समिति

संपादकीय समिति की गठन निम्नलिखित संरचना और कार्यों के साथ किया जाएगा :

##### 6.2.1 संरचना

- |  |            |
|--|------------|
| 1. समिति का एक वरिष्ठ सदस्य                        | सभापति     |
| 2. इतिहास/अभिलेखागार के क्षेत्र से संबंधित 2 सदस्य | सदस्य      |
| 3. अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार          | सदस्य सचिव |

##### 6.2.2 कार्य

संपादकीय समिति आईएचआरसी के सदस्यों द्वारा अथवा अन्य अध्येताओं द्वारा लिखित और उनके माध्यम से प्रेषित सभी शोध पत्रों की आईएचआरसी के अकादमिक सत्रों में प्रस्तुत करने के लिए समीक्षा करेगी।

यह आईएचआरसी के अकादमिक सत्रों में प्रस्तुत किए गए सभी शोध की भी समीक्षा करेगी और इसे समिति की कार्यवाहियों में पूर्णतः अथवा सार के रूप में शामिल किया जाना है, इसकी सिफारिश करेगी।

सामान्यतः संपादकीय समिति की बैठकें वर्ष में दो बार होंगी।

#### 7.0 सवारी भत्ता :

पदेन सभापति, सचिव, संस्कृति मंत्रालय (स्थायी समिति के पदेन सभापति) पैरा 2.2 में उल्लिखित भारत सरकार के नामिति और स्थायी समिति के अन्य सदस्य जो सरकारी अधिकारी हैं तथा समिति और इसकी समितियों की बैठक/बैठकों में भाग लेते हैं, तो तत्संबंधी प्रभार केंद्रीय राजस्व पर जाएगा और इस पर आने वाला खर्च उनके वेतन की भांति उसी शीर्ष में डेबिट योग्य होगा।

भारत सरकार द्वारा आईएचआरसी अथवा इसकी समितियों सदस्यों के रूप में नामित और गैर सरकारी व्यक्तियों को समिति अथवा इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए केंद्र सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को अनुमेय सवारी भत्ते की दर से सवारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा तथा केंद्र सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को संबंधित स्थानों के लिए अनुमेय दैनिक भत्ते की उच्चतम दर से दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य घटक संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने नामितियों के सवारी भत्ते का वहन करें। केंद्र सरकार के नामितियों के अलावा गैर सरकारी सदस्यों, जिन्हें भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति की किसी समिति में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, को सवारी भत्ते का भुगतान उसी दर से किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा साधारण सदस्यों के रूप में नियुक्त गैर सरकारी सदस्यों को किया जाता है।

### कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक

सं. एमएसडीई (डीजीटी)-19/17/2016-सीडी—श्रम मंत्रालय के दिनांक 21/24 अगस्त 1956 के संकल्प सं. टीआर/ईपी-24/56 के आंशिक आशोधन द्वारा 27 अप्रैल, 2020 तक किए गए संशोधन से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) इसके उपरान्त 10 नवम्बर, 2017 से निम्न प्रकार संशोधित रहेगी। परिषद में अब निम्न सदस्य होंगे:-

- |  |             |
|--|-------------|
| (क) केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री                     | - अध्यक्ष   |
| (ख) केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री               | - उपाध्यक्ष |
| (ग) सचिव, एमएसडीई  | - सदस्य     |
| (घ) महानिदेशक/अपर सचिव, (एमएसडीई) प्रशिक्षण महानिदेशालय            | - सदस्य     |
| (ङ) महानिदेशक/अपर सचिव, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेन्सी (एनएसडीए)     | - सदस्य     |
| (च) वित्तीय सलाहकार, एमएसडीई                                       | - सदस्य     |
| (छ) निम्न में प्रत्येक से एक प्रतिनिधि:                            |             |
| (i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय                           | - सदस्य     |
| (ii) वस्त्र मंत्रालय   | - सदस्य     |
| (iii) स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय | - सदस्य     |
| (iv) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय                                      | - सदस्य     |
| (ज) निम्न राज्यों में से एक-एक प्रतिनिधि:                          |             |
| (i) उत्तर प्रदेश   | - सदस्य     |
| (ii) बिहार   | - सदस्य     |
| (iii) महाराष्ट्र   | - सदस्य     |
| (iv) गुजरात  | - सदस्य     |
| (v) हरियाणा  | - सदस्य     |
| (vi) उड़ीसा  | - सदस्य     |
| (vii) कर्नाटक  | - सदस्य     |
| (viii) तमिलनाडु  | - सदस्य     |
| (ix) सिक्किम तथा   | - सदस्य     |
| (x) दिल्ली (संघ शासित प्रदेश)                                      | - सदस्य     |
| (झ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से एक प्रतिनिधि               | - सदस्य     |
| (ञ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से एक प्रतिनिधि      | - सदस्य     |

(ट) नियोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि	- सदस्य
(ठ) कामगार संगठनों से दो प्रतिनिधि	- सदस्य
(ड) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से दो प्रतिनिधि (प्रत्येक श्रेणी से एक)	- सदस्य
(ढ) अखिल भारतीय महिला संगठन के दो प्रतिनिधि	- सदस्य
(ण) दो विशेषज्ञ	- सदस्य
(त) निदेशक (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण महानिदेशालय	- सदस्य सचिव

परिषद के सभी गैर-सरकारी सदस्यों अथवा परिषद द्वारा नियुक्त किसी भी उप समिति की कार्यावधि वर्तमान परिषद के कार्यकाल अर्थात् 27 अप्रैल, 2020 तक होगी।

विजय कुमार देव  
महानिदेशक/अपर सचिव



MINISTRY OF CULTURE  
(NATIONAL ARCHIVES OF INDIA)  
New Delhi-110001, the 19th December 2017

RESOLUTION

Constitution of the Indian Historical Records Committee.

No. 19-1/2016-CC—In supersession of this Ministry's Resolution No. F 19/2007 CC dated 04.07.2011, the Government of India has reconstituted the Indian Historical Records Committee, as per Annexure.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Part-1 Section-1

S. C. MONDAL, Under Secretary

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA  
INDIAN HISTORICAL RECORDS COMMITTEE  
(IHRC)

CONSTITUTION

(As Approved On 2 November 2017)

1.0 Background

The Indian Historical Records Commission (re-designated Indian Historical Records Committee), was set up by the Government of India in 1919 (vide Department of Education Resolution No.77, dated 21 March 1919) as a consulting body, whose opinion would carry weight with the public and which would make enquiries and recommendations regarding:

- i. treatment of archives for historical study,
- ii. the scale and plan on which the cataloguing, the calendaring and reprinting of each class of documents should be undertaken,
- iii. the sums required for encouraging research among, and publication of records,
- iv. selection of competent scholars for editing documents, and
- v. the problems of public access to records.

With a view to promoting active cooperation of the various State Governments in India as also the universities and learned institutions in the country in the activities of the Committee, the Government of India (vide their Department of Education, Health and Lands, Resolution No. F.92-9/40-E, dated 10 September 1941), took steps to reform the Constitution of the Committee by providing for the inclusion of nominees of the various State Governments in India as also those of the Universities and Learned Societies.

The INDIAN HISTORICAL RECORDS COMMITTEE<sup>1</sup> (hereafter IHRC) has, over the years, contributed significantly to the growth of public interest in the conservation and use of archives. The Government of India do recognize that it was through the initiative of the IHRC and its different Committees that many new sources of information have been brought to light and saved for posterity, many collections of documents have been published and made accessible to scholars, facilities for the use of records have been materially enhanced and a new conscience has been aroused in the public mind in respect of the sanctity of historical evidence. While the Government of India notes with deep appreciation these and other achievements of the Committee, they do feel at the same time that much work still remains to be done and that a host of important problems are still awaiting to be tackled. Very little systematic effort has been made to survey, describe, organize or make use of records in private custody, and particularly, those of institutional, religious or commercial origin. Lack of trained archivists continues seriously to impede the archival work in the country and the training facilities available in the National Archives of India have hardly stimulated an adequate response among the owners of archival holdings. The Government believes that these constitute very serious lacunae in the academic life of the nation and that greater and more whole-hearted cooperation between the custodians of records and historical materials on the one hand and their users on the other, is the only means by which these deficiencies could be removed.

<sup>1</sup> As amended vide Department of Culture, Government of India, Resolution No. F.32-34/84-Lib. (P&A), dated 15.10.1990 and corrigendum, dated 14.02.1992; F.18-15/96-Lib.II, dated 25.11.96; F.No. 18-20/2002-A&A, dated 10.06.2002; and National Archives of India, F.Nos. 19/2007-CC, dated 12.06.2009, and 4.07.2011. F. No. 18-26/2017-A&A dated 02.11.2017.

In order to promote such cooperation the Government of India, in supersession of all earlier Resolutions on the same subject, is pleased to sanction a reconstitution of the IHRC on the following lines:

## 2.0 COMPOSITION

The IHRC shall consist of the following Members:

### 2.1. Ex-Officio Members

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Minister of Culture, Government of India..... | Chairperson       |
| 2. Secretary (Culture), Government of India..... | Member            |
| 3. Director General of Archives.....             | Member -Secretary |

### 2.2. Nominees of the Government of India

10 eminent archivists and historians to be appointed by the Government of India on the basis of their specialized knowledge of the treatment of archives or their original contribution to the post-1600 period of Indian History.

### 2.3. Central Government Nominees

Three representatives of the following agencies of the Government of India:

1. Ministry of Home Affairs
2. Ministry of Defence
3. Department of Administrative Reforms and Public Grievances

### 2.4. Nominees of the State Governments/Union Territories Administrations

Representatives from all State Governments/Union Territories Administrations that have an organized records repository of their own. These nominee should invariably be the custodian of the Archives of the State/ Union Territory.

### 2.5. Nominees of Universities

70 nominees from Universities in India teaching post-1600 period of Indian History and encouraging research and publication of original records, and co-operating with the IHRC in organizing its own archives.

### 2.6. Nominees of the Learned Institutions

20 nominees from Learned Institutions with proven contribution for encouraging historical research, publication and in conducting survey and exploration of records in private and semi-private custody.

Note (Paras 2.5 and 2.6): The nominees of the Universities, and Learned Institutions should be persons of academic distinction with considerable amount of original research work to their credit. All such nominees will become members of the IHRC only after their nominations have been approved and notified by the Government of India.

## 3.0 TERM OF THE IHRC

The Members of the Committee, other than ex-officio Members will be appointed for a term of five years as follows:

All appointments and re-appointments for a full term of five years will be en-bloc with effect from the same date. Vacancy due to resignation or otherwise which may occur during the said period of five years will not be filled for another term of five years but only for the unexpired period of the existing term.

## 4.0 SCOPE OF THE IHRC

- a To act as a forum for exchange between creators, custodians and users of archives and historical documents, of ideas and experiences relating to treatment, preservation and use of archives, and to make recommendations to appropriate bodies, official or non-official in this behalf.
- b To act as a forum for discussion on archives in relation to historical problems requiring investigation, particularly in relation to those on which little or no work has been done, and to hold Academic Sessions. At this Academic Session, papers based on newly discovered original records pertaining to the post-1600 period of Indian history be read and discussed. These papers should be written either by the Members of the IHRC or communicated through them if written by other scholars. All such papers should be circulated in advance after getting them approved by an EDITORIAL COMMITTEE to be constituted for the purpose (See Para 6.2 below).
- c To promote the salvaging and use of material in private and semi-public custody (including institutional, religious and business records) in collaboration with universities, libraries, museums, learned societies, and similar local bodies, and to act as a disseminator of information on the work done in this field.
- d To act generally as an intermediary between records and historical manuscript repositories on the one hand, and bodies interested in research on the other.
- e To publish proceedings and bulletins embodying reports on its activities and on other matters promoting its objectives.

## 5.0. MEETINGS OF THE IHRC

The IHRC shall normally meet once a year at a place rich in archival materials being selected as the venue. Each session should include:

- a. A Public Meeting devoted to the report to be presented by the Secretary on the archival progress in the country.
- b. A Business Meeting for the discussion of the Secretary's Report as also the problems relating to keeping and use of archives that may be referred to it by the members and for review of programmes undertaken by different bodies under its auspices.
- c. Academic Session(s) for reading and discussion of research papers based on original records pertaining to the post-1600 period of Indian history. Such sessions shall be open to the interested public.

The Meetings of the IHRC are to be presided over by the ex-officio President. He shall however, have the right to nominate a senior Member of the IHRC to act as President in his absence.

## 6.0. COMMITTEES OF THE IHRC

The IHRC may appoint one or more Committees to deal with the particular problems requiring investigation. Such Committees shall submit their reports to the Committee.

### 6.1. STANDING COMMITTEE

The STANDING COMMITTEE shall be set up with the following composition and functions:

#### 6.1.1 Composition

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Secretary, Ministry of Culture, Government of India.....                             | Ex Officio Chairman        |
| b. 5 Members of the IHRC to be nominated by the Government of India.....                | Members                    |
| c. Director General of Archives.....  | Ex-Officio Secretary       |
| d. Deputy Director of Archives, National Archives of India (dealing with the Committee) | Ex Officio Joint Secretary |

#### 6.1.2 Functions

The Standing Committee will review the action taken from time to time on the recommendations made by the IHRC, consider all reports and items referred to it, express its views on the agenda for the IHRC's meeting, and perform such other functions as the Government of India or the President of the Committee may assign to it.

The Standing Committee will ordinarily meet twice a year.

### 6.2. Editorial Committee

The EDITORIAL COMMITTEE shall set up with the following composition and functions:

#### 6.2.1 Composition

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. A Senior Member of the IHRC .....                              | Chairman         |
| 2. Two members representing the fields of history/ archives ..... | Members          |
| 3. Director General of Archives .....                             | Member Secretary |

#### 6.2.2 Functions

The Editorial Committee will review all research papers submitted by the Members of the IHRC or communicated through them, if written by other scholars, for presentation at the Academic Session(s) of the IHRC.

It will also review all papers that are presented at the Academic Session(s) of the IHRC and recommend whether it has to be included in published Proceedings of the IHRC in full form or as an Abstract.

The Editorial Committee will ordinarily meet twice a year.

## 7.0. TRAVELLING ALLOWANCE

The travelling allowance of the Ex-Officio President, Secretary, Ministry of Culture (Ex- Officio Chairman of the Standing Committee), the nominees of the Government of India, referred to in Para 2.2 and such members of the Standing Committee who are Government officials attending the meeting(s) of the IHRC and its Committees will be charged on the Central Revenues, and the expenditure for the same will be debitable to the same head as their pay.

Non-officials appointed by the Government of India as Members of the IHRC or its Committees will draw travelling allowances for attending meetings of the IHRC or its Committees at rates admissible to Grade-I Officers of the Central Government and daily allowances at the highest rate admissible to Grade-I Officers of the Central Government for respective localities. The expenditure will be met from the budget grant of the National Archives of India. The State Governments, the

Universities and other Constituent Institutions will be required to bear the travelling allowances of their nominees. The travelling allowance for non-official members other than Central Government nominees who may be appointed to serve on any Committee of the IHRC will be paid at the same rate as those of non-official members appointed by the Central Government as Ordinary Members.

## MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

New Delhi, the \_\_\_\_\_

No. MSDE(DGT)-19/17/2016-CD—In partial modification of Ministry of Labour Resolution No. TR/EP-24/56 dated 21st/24th August 1956 and amended up to 27th April, 2020, the National Council for Vocational Training (NCVT) shall hereinafter stand amended as under, with effect from 10th November, 2017. The Council shall now consist of following members:—

- |       |  |                  |
|-------|--|------------------|
| a)    | Union Minister of Skill Development and Entrepreneurship                       | Chairman         |
| b)    | Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship                   | Vice-Chairman    |
| c)    | Secretary, MSDE  | Member           |
| d)    | Director General/Additional Secretary, Directorate General of Training         | Member           |
| e)    | Director General/Additional Secretary, National Skill Development Agency(NSDA) | Member           |
| f)    | Financial Advisor, MSDE  | Member           |
| g)    | One representative each of:  |                  |
| i.    | Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises                                  | Member           |
| ii.   | Ministry of Textiles   | Member           |
| iii.  | Department of School Education & Literacy, Ministry of HRD                     | Member           |
| iv.   | Ministry of Labour & Employment  | Member           |
| h)    | One representative each from State of:   |                  |
| i.    | Uttar Pradesh  | Member           |
| ii.   | Bihar  | Member           |
| iii.  | Maharashtra  | Member           |
| iv.   | Gujarat  | Member           |
| v.    | Haryana  | Member           |
| vi.   | Odisha   | Member           |
| vii.  | Karnataka  | Member           |
| viii. | Tamil Nadu   | Member           |
| ix.   | Sikkim &   | Member           |
| x.    | Delhi (Union Territory)  | Member           |
| i).   | One representative of All India Council for Technical Education                | Member           |
| j).   | One representative of Central Board of Secondary Education (CBSE)              | Member           |
| k).   | Two representatives of Employers Organizations                                 | Members          |
| l).   | Two representatives of Workers Organizations                                   | Members          |
| m).   | Two representatives of SC & ST (one from each category)                        | Members          |
| n).   | Two representative of All India Women Organization                             | Members          |
| o).   | Two Experts  | Members          |
| p).   | Director (Training), Directorate General of Training                           | Member Secretary |

The term of office of all non-official members of the Council or any Sub Committee appointed by the Council shall be upto the tenure of present council i.e. 27th April, 2020.

VIJAY KUMAR DEV  
Director General/Additional Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2018  
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2018

www.dop.nic.in